GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

## EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS



Tel: 91-11-26135256 Fax: 91-11-26135518,26135519

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 Email: press@epch.com web: www.epch.in

## **EPCH PRESS RELEASE**

#### CONTAINERS CRISES, FREIGHT COST HAMPERS HANDICRAFTS GROWTH

NEW DELHI - 30th March 2021 - In order to ensure that handicrafts sector keeps growing at a brisk pace and continue to earn much needed foreign exchange and provide livelihood to millions of craftspersons, it is important that the logistic system (availability and movement of containers) should support and compliment the efforts made by the artisans and exporters.

Mr. Ravi K Passi, Chairman-EPCH drew attention of the Hon'ble Minister of Railways, Commerce & Industry towards the problem of the shortage of availability of containers for exports and said that the current Covid crisis has resulted in stalling the exports growth and despite business activity picking pace in the 2<sup>nd</sup> quarter onwards, any disruption at this critical stage in shipments would deal a severe blow to all the export promotion efforts of all the stakeholders. Adding further he said, any delay in Shipment may also lead to the cancellation in export orders as well.

He thanked the Hon'ble Minister for his intervention in the past but drew his attention towards one important problem that is hampering export growth is the charges being levied by the shipping lines for each container as the sea freight charges has increased manifold clearly indicating unfair trade practice by shipping lines. The problem is further being compounded with the increase in Raw Material prices. He urged the Government to urgently look into the matter, so that exports from the country can continue without any hindrance and help facilitate timely shipments of the export consignments and thereby promote exports from the country.

He further requested the Government to consider establishment of a Regulatory Authority through enactment of the Parliament to control and monitor the pricing, terms & conditions and other provisions relating to the shipment of goods. The current shipping lines are arbitrarily deciding the pricing and imposing conditions at their whims and fancies.

The estimated figures for exports of handicrafts for the period April-February of the current financial year 2020-21 which stands at Rs. 22774.58 crores (USD 3062.76 million) registering a negative growth of (-)3.40 % (Rupee terms) and (-)8.31% (dollar terms) over the same period last year.

#### For more information, please contact:

Dr. Rakesh Kumar, Director General - EPCH - +91-9818272171













# ईपीसीएच प्रेस विज्ञप्ति

# कंटेनर संकट और बढ़ा किराए भाड़ा बने हस्तशिल्प विकास में बाधक

नई दिल्ली- 30 मार्च 2021- हस्तशिल्प सेक्टर के सतत और तेज गति से विकास और लाखों कारीगरों और शिल्पियों की रोजीरोटी के साथ देश के लिए बहुत जरुरी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह जरुरी है कि लॉजिस्टिक सिस्टम (कंटेनरों की उपलब्धता और उनका परिचालन) लगातार करीगरों और निर्यातकों के हस्तशिल्प को लेकर किए गए प्रयासों का सहयोग और समर्थन करने में सक्षम हो।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के चेयरमैन श्री रिव के पासी ने रेलवे एवं वाणिज्य तथा उद्योग के माननीय केंद्रीय मंत्री का ध्यान निर्यात के लिए कंटेनरों की कमी होने की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड महामारी के परिणाम स्वरुप निर्यात की विकास दर रुक सी गयी है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में व्यवसायिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी है लेकिन इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अगर शिपमेंट के स्तर पर किसी तरह का व्यवधान आता है तो यह निर्यात को प्रोत्साहित करने के सभी हितधारकों के संपूर्ण प्रयासों पर एक गहरा कुठाराघात होगा। अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि शिपमेंट में किसी भी तरह की और देरी से एक्सपोर्ट आर्डर्स रद भी हो सकते हैं।

उन्होंने अतीत में निर्यातकों के हित के लिए माननीय मंत्री को सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर उनका ध्यान भी आकर्षित किया जो निर्यात वृद्धि में बाधक है, ये समस्या प्रत्येक कंटेनर के लिए शिपिंग लाइनों द्वारा लगाया जा रहा शुल्क है जिससे समुद्र भाड़ा शुल्क कई गुना बढ़ गया है। यह शिपिंग लाइन्स द्वारा स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार का पर्याय है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इस समस्या को और जटिल बना रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस समस्या को दृष्टिगत करने का आग्रह किया, ताकि देश से निर्यात बिना किसी बाधा के जारी रह सके और निर्यात खेपों के समय पर लदान की सुविधा प्रदान कर सके और जिससे देश से निर्यात को बढावा मिले।

उन्होंने आगे सरकार से अनुरोध किया कि वस्तुओं के शिपमेंट से संबंधित मूल्य निर्धारण, नियमों और शर्तों और अन्य प्रावधानों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए संसद के अधिनियम के माध्यम से एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करें। वर्तमान समय में शिपिंग लाइन्स मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारण कर रही हैं और मनमाने तरीकों से ही निर्यातकों पर शर्तें लागू कर रही हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के अप्रैल से फरवरी तक की अवधि में हस्तशिल्प निर्यात का अनुमानित आकंड़ा इस समय 22774.58 करोड़ रुपये यानी 3062.76 मिलियन डालर है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अविध के सापेक्ष रुपयों के लिहाज से (-)3.40 प्रतिशत और डालर के हिसाब से (-)8.31 प्रतिशत ऋणात्मक विकास दर को दर्शाता है।

ज्यादा जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

डॉ. राकेश कुमार, महानिदेशक, ईपीसीएच - +91-9818272171











Copyright 2020 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.



